प्रसार भारती
प्रादेशिक समाचार एकांश
आकाशवाणी रायपुर (छत्तीसगढ़)
प्रादेशिक समाचार बुलेटिन

19.10 सोमवार **दिनांक 30.06.2025**

मुख्य समाचारः–

- **राज्य में कृषक उन्नति योजना का दायरा बढ़ा–धान के साथ ही दलहन, तिलहन, मक्का आदि की फसल लगाने वाले किसानों को भी मिलेगा इसका लाभ।**

- **केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हथियारबंद माओवादियों से कोई बातचीत नहीं की जाएगी।**

- **केन्द्र सरकार ने राज्य के मुख्य सचिव अमिताभ जैन को तीन महीने का सेवा विस्तार दिया।**

- **सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि डीएपी खाद की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में किसानों को वैकल्पिक खाद उपलब्ध कराई जाए।**

राज्य मंत्रिपरिषद–निर्णय–

प्रदेश में कृषक उन्नति योजना का लाभ अब धान उत्पादक किसानों के साथ ही दलहन, तिलहन, मक्का आदि की फसल लगाने वाले किसानों को भी मिलेगा। यह निर्णय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में हुई राज्य मंत्रिपरिषद के बैठक में लिया गया।

बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में पेश है

राज्य सरकार ने कृषक उन्नति योजना का दायरा बढ़ा दिया है। मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद फैसलों की जानकारी देते हुए उपमुख्यमंत्री अरूण साव ने बताया कि खरीफ वर्ष दो हजार चौबीस में पंजीकृत

किसान जिन्होंने धान की फसल लगाई थी और समर्थन मूल्य पर धान बेचा था, उनके द्वारा चालू खरीफ में धान फसल के स्थान पर दलहन, तिलहन, मक्का आदि फसल की खेती की जाती है, तब भी उन्हें कृषक उन्नति योजना के तहत आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

श्री साव ने बताया कि मंत्रिपरिषद के एक अन्य फैसले में छत्तीसगढ़ पेंशन फंड के गठन तथा इसके प्रबंधन और विनियमन संबंधी विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। यह कदम सरकारी अधिकारियों–कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के समय पेंशन भुगतान संबंधी दायित्वों के बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए उठाया गया है। इसके साथ ही राज्य के दीर्घकालिक आर्थिक विकास और राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड के गठन तथा इसके प्रबंधन और विनियमन संबंधी विधेयक के प्रारूप का भी अनुमोदन किया गया। इससे राजस्व में असामान्य वृद्धि या कमी का समुचित प्रबंधन और आर्थिक मंदी के समय वित्तीय सुरक्षा प्राप्त होगी।

राज्य मंत्रिपरिषद–निर्णय–

मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य में लॉजिस्टिक सेक्टर के समग्र विकास के लिए छत्तीसगढ राज्य लॉजिस्टिक पॉलिसी के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इस पॉलिसी से छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित होगा तथा निर्यात अधोसंरचना को मजबूती मिलेगी। इस नीति के माध्यम से ड्राई पोर्ट/इन्लैण्ड कंटेनर डिपो की स्थापना को प्रोत्साहित करने से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों तथा स्थानीय उत्पादकों को निर्यात बाजारों तक पहुंचने का अवसर मिलेगा। राज्य के प्रचुर वन संसाधन, वनोपज और वनौषधि उत्पाद के निर्यात हेतु इको सिस्टम तैयार होगा।

मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के कुछ कानूनों के प्रावधानों का गैर–अपराधीकरण करने के लिए छत्तीसगढ़ जन विश्वास विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

मुख्य सचिव–अमिताभ जैन

केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन के सेवा विस्तार को मंजूरी दे दी है। उपमुख्यमंत्री अरूण साव ने बताया कि आज राज्य कैबिनेट की बैठक में अमिताभ जैन को मुख्य सचिव के पद पर तीन महीने का सेवा विस्तार देने का निर्णय लिया गया।

गौरतलब है कि मुख्य सचिव अमिताभ जैन आज सेवानिवृत्त होने वाले थे।

केन्द्रीय गृहमंत्री–माओवाद

केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हथियारबंद माओवादियों से कोई बातचीत नहीं की जाएगी। उन्होंने तेलंगाना के निजामाबाद में किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासियों, पुलिसकर्मियों और सुरक्षाकर्मियों की हत्या करने वालों से कोई बात नहीं हो सकती। केन्द्रीय गृहमंत्री ने वामपंथी उग्रवादियों से हथियार छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होने का आह्वान किया।

सारे लोग हथियार छोड दो और सरेंडर करो अगर सरेंडर नहीं करेंगे तो हमने तय किया है कि 31 मार्च 2026 के पहले इस देश से नक्सलवाद को हम समाप्त कर देंगे। हमारी सरकार का नीति है, जिनके हाथ में हथियार है, उनसे कोई बातचीत नहीं होगी।

केन्द्रीय कोयला मंत्री–मुख्यमंत्री मुलाकात

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आज रायपुर स्थित उनके निवास में केन्द्रीय कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चन्द्र दुबे ने भेंट की। इस दौरान राज्य में कोयला खनन और उत्पादन से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार–विमर्श हुआ।

बैठक में राज्य में कोयला उत्पादन, खनन कार्यों की प्रगति, श्रमिकों से जुड़ी सुविधाओं और विकास कार्यों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में कोयला और ऊर्जा क्षेत्र में विकास की संभावनाओं को साकार करने में सहायता मिलेगी। इस अवसर पर सीएसआर मद की राशि का उपयोग अधिक से अधिक जनकल्याणकारी कार्यों में करने के संबंध में विशेष रूप से चर्चा की गई।

सहकारिता मंत्री–डीएपी

सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीएपी खाद की कमी के कारण यदि प्रदेश में डीएपी खाद की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पा रही है तो डीएपी के विकल्प के प्रति किसानों को जागरूक किया जाए। श्री कश्यप ने नवा रायपुर में सहकारिता और उर्वरक कंपनियों के अधिकारियों की बैठक लेकर निर्देश दिए कि किसानों को वैकल्पिक खाद उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि रासायनिक खाद की कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले अधिकारियों–कर्मचारियों और केन्द्र संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

केन्द्रीय मंत्री–दौरा

केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले कल एक दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर रायपुर आ रहे हैं। वे कल राजधानी में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित योजनाओं की समीक्षा के लिए राज्य शासन के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। केन्द्रीय मंत्री कल शाम ही रायपुर से मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे।

संविधान हत्या दिवस

भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा कांग्रेस सरकार द्वारा उन्नीस सौ पचहत्तर में लगाए गए आपातकाल के पचास साल पूरा होने पर दो जुलाई को रायपुर के अग्रसेन धाम में ''युवा संसद'' का आयोजन किया जाएगा। इस एक दिवसीय कार्यक्रम में प्रदेशभर से युवा प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस युवा संसद का उद्देश्य आपातकाल के दौरान हुई ज्यादतियों और नागरिकों को मिले संवैधानिक अधिकारों को कुचलने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में युवाओं को जानकारी देना है।

गौरतलब है कि पच्चीस जून उन्नीस सौ पचहत्तर को देशभर में इमरजेंसी यानी आपातकाल लागू किया गया था। इस दौरान विपक्षी पार्टियों के अनेक नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया, जिन्हें मीसाबंदी कहा जाता है। आपातकाल के विरोध में देशभर में बीते पच्चीस जून को संविधान हत्या दिवस मनाया गया। धमतरी से मीसाबंदी रहे स्वर्गीय हनुमान प्रसाद मिश्रा के पौत्र रोहिताश मिश्रा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए बताया कि आपातकाल के समय भय का माहौल था।

टीबी–बीपालएम रेजिम

राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत नोडल डीआरटीबी सेंटर, मेकाहारा, रायपुर में दवा प्रतिरोधक टीबी के मरीजों के लिए नये बीपालएम रेजिम की शुरुआत की गई है। पहले टीबी के दवा प्रतिरोधी मरीजों को नौ से अट्ठारह महीने तक पांच से सात दवाएं प्रतिदिन लेनी पड़ती थीं। लेकिन बीपालएम रेजिम के तहत इलाज की अवधि केवल छह माह रह गई है और अब केवल चार आधुनिक दवाओं से इलाज संभव होगा। इन दवाओं की अनुमानित लागत एक लाख रुपये से अधिक है, जिसे सरकार की ओर से पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है।

<u>ग्रामीण–प्रदर्शन</u>

जांजगीर–चाम्पा मुख्य मार्ग पर जर्वे गांव के ग्रामीणों ने खराब सड़क के मुद्दे पर आज चक्काजाम किया। विधायक व्यास कश्यप के नेतृत्व में ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर नारेबाजी की। जिले के अपर कलेक्टर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत की। आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने चक्काजाम समाप्त किया।

<u>कवासी लखमा–चालान</u>

शराब घोटाला मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के खिलाफ आज आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो–ईओडब्ल्यू ने चौथा पूरक चालान पेश किया। विशेष कोर्ट में ग्यारह सौ पन्नों का चालान पेश किया गया। इस चार्जशीट में लखमा की भूमिका का उल्लेख किया गया है।

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>